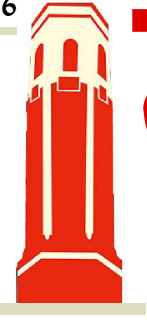


- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 259
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

अघोषित इमरजेंसी : दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन, गिरफ्तारी

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली/देहरादून। लोकतंत्र की असली कसौटी सत्ता के सामने उठने वाले सवालों से तय होती है। सरकार की नीतियों का विरोध, असहमति की आवाज और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी पहचान हैं। लेकिन जब विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियों की खबरें सामने आती हैं और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल

◆सरकार की कार्रवाई और नागरिक अधिकारों के बीच टकराव बना राजनीतिक बहस का केंद्र
◆जंतर-मंतर से उठी बहस, राजधानी में सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा, हिरासत में लिए गए कई लोग

उठने लगते हैं, तो बहस केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहती। सवाल यह भी उठता है कि क्या असहमति के लिए लोकतांत्रिक जगह लगातार सिमट रही है?

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों ने इसी बहस को फिर तेज किया है। विपक्षी दलों और सरकार के आलोचकों की ओर से ऐसी परिस्थितियों को अघोषित इमरजेंसी की संज्ञा दी जा रही है। उनका आरोप है कि असहमति जताने वालों पर कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और विरोध की आवाज को सीमित करने की कोशिशें लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय हैं। दूसरी ओर, सरकार और प्रशासन की ओर से ऐसी कार्रवाइयों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा लागू कानूनी प्रावधानों के तहत उचित ठहराया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आरोपों और सरकारी दलीलों की जांच तथ्यों, कानूनी आधार और नागरिक अधिकारों की कसौटी पर की जाए।

दिल्ली में काकाचोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले जिस स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई, उसने राजनीतिक टकराव को नया आयाम दे दिया। प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर है। प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। दो अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था। द वीक की रिपोर्ट के अनुसार, उस दिन 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने

अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रंका और यूट्यूबर ध्रुव राठी हिरासत में !



संवाददाता

नई दिल्ली। सीजेपी का दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज यानी 10 अक्टूबर को प्रोटेस्ट है। जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले ही दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। जंतर-मंतर पर काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके को दिल्ली पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया है। वे करीब सुबह 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें बाहर निकलने से पहले ही डिटेन कर लिया गया। इसके अलावा सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रंका को भी हिरासत में लिया गया है। फ्लाइट के अंदर का वीडियो सामने आया है, जिसमें दीपके कह रहे हैं कि मैं अरेस्ट होने के लिए आया हूँ, कर लो अरेस्ट, मैं डरता नहीं हूँ। सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह दिल्ली स्थित आवास से हिरासत में ली गई। सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस सख्ती बरत रही है। यूट्यूबर ध्रुव राठी को पहले ही हिरासत में ले चुकी है। इसके अलावा 1000 अन्य समर्थकों को भी राजधानी के अलग-अलग स्थानों

की खबर थी। वहीं, 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले भी पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की।

प्रदर्शन से पहले राजधानी में हजारों पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की

से पकड़ा गया है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पोस्ट कर ध्रुव राठी की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, एक चोर दूसरे चोर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। देश के युवाओं की बुलंद आवाज ध्रुव राठी को मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया है।

मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने सीजेपी

के प्रदर्शन से पहले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन हिरासतों को पूरी तरह गैरकानूनी बताते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार के इशारे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के जरिए लोकतंत्र को हड़पने के खिलाफ होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत भूषण ने कहा कि मोदी और शाह जनता से इतने डरे हुए हैं।

राहुल गांधी ने कहा- यह सरकार जाएगी!

नई दिल्ली। चेन्नई में छात्रों के 'गूँज' कार्यक्रम में शामिल होने से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, ज्ञानेश कुमार जाएंगे। यह सरकार जाएगी। फिर लोकतंत्र को दुरुस्त करने का काम शुरू होगा। राहुल गांधी ने एक्स पर केवल लिखित संदेश ही साझा नहीं किया, बल्कि संसद के सेंट्रल हॉल में इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच दिए गए अपने भाषण की एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट की। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी अधिक गंभीर समस्या मौजूद है और उसका समाधान मौजूदा सरकार को हटाने से जुड़ा है। राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों से कहा था कि पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की ओर से किए गए प्रदर्शनों ने सरकार की नींव हिला दी है और सरकार दबाव में है। उन्होंने इस संघर्ष को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि इसके लिए संघर्ष करना और जरूरत पड़ने पर जान देना भी सार्थक है।

तैनाती, सड़कों पर अवरोधक, यातायात में बदलाव और कुछ मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध जैसी व्यवस्थाएं की गईं। जनपथ-कर्तव्य पथ क्षेत्र के चार किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी

निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किए जाने की खबर आई। इन कदमों का उद्देश्य प्रशासन की ओर से संभावित अव्यवस्था को रोकना बताया गया। यही वह बिंदु है जहां सरकार और उसके आलोचकों के

तर्क आमने-सामने हैं। प्रशासन के सामने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और संभावित हिंसा या अव्यवस्था को रोकने की जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी के निर्वहन में यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि शांतिपूर्ण विरोध करने और अपनी बात रखने के संवैधानिक अधिकार का अनावश्यक हनन न हो।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्वक और बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर कानून के तहत उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए किसी कार्रवाई की वैधता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि पुलिस तैनात थी या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। यह भी देखना होगा कि प्रतिबंध का आधार क्या था, कार्रवाई कितनी आवश्यक और आनुपातिक थी तथा हिरासत में लिए गए लोगों के कानूनी अधिकारों का पालन हुआ या नहीं। दिल्ली की घटना ने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है। यदि किसी संगठन के प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, तो प्रशासन को उसे नियंत्रित करने का अधिकार है। लेकिन क्या आशंका के आधार पर व्यापक प्रतिबंधों और धरपकड़ को सामान्य प्रशासनिक उपाय मान लिया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ठोस तथ्यों और कार्रवाई की स्वतंत्रता से ही मिल सकता है। विपक्षी दलों और आंदोलनकारियों की ओर से इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश बताया जा रहा है। दूसरी ओर, पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के पीछे प्रक्रियागत खामियों और कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है।

ऐसे में अघोषित इमरजेंसी का आरोप राजनीतिक बहस का हिस्सा है, लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए व्यापक और प्रमाणित साक्ष्यों की जरूरत होगी। फिर भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि लोकतंत्र में विरोध की अनुमति, पुलिस की जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि असहमति के अधिकार की रक्षा करने से भी तय होती है। सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन नागरिकों के लिए यह भरोसा भी उतना ही जरूरी है कि शांतिपूर्ण सवाल पूछना अपने आप में अपराध नहीं है। दिल्ली का घटनाक्रम इसी संतुलन की परीक्षा ले रहा है।

दून वैली मेल

संपादकीय

बाजार की जंग में सत्ता पर सवाल

दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क ने भारत के दूरसंचार बाजार को लेकर एक ऐसा सवाल खड़ा किया है, जो किसी एक कंपनी या कारोबारी प्रतिद्वंद्विता तक सीमित नहीं है। स्पेसएक्स की उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलैंक की भारत में शुरुआत को लेकर जारी खींचतान के बीच मस्क ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चैयरमैन मुकेश अंबानी को निशाने पर लेते हुए उन्हें व्यंग्यात्मक अंदाज में डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी और भारत का असली बास कह दिया। उनका आरोप है कि अंबानी भारतीय दूरसंचार बाजार में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। यह आरोप मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लगाया है। इसे स्थापित तथ्य नहीं, बल्कि एक कारोबारी पक्ष का आरोप मानकर ही देखा जाना चाहिए। मस्क की इस टिप्पणी में व्यंग्य है, कारोबारी आक्रामकता है और भारतीय बाजार में प्रवेश को लेकर उनकी बेचौनी भी दिखाई देती है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत जैसे विशाल बाजार में प्रतिस्पर्धा के नियम कौन तय करता है और उनका पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या किसी स्थापित कारोबारी समूह की बाजार में मजबूत स्थिति नए प्रतिस्पर्धियों के लिए बाधा बन रही है, या फिर नियामकीय मंजूरीयों की प्रक्रिया को लेकर एक विदेशी कंपनी अधीर हो रही है? इन सवालों का जवाब सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों से नहीं, बल्कि तथ्यों, नियमों और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया से मिलना चाहिए। भारत में इंटरनेट अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, व्यापार और सूचना तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। देश के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों, सीमांत गांवों और उन इलाकों में जहां पारंपरिक दूरसंचार ढांचा पहुंचाना कठिन है, उपग्रह इंटरनेट नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में इसकी उपयोगिता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। आपदा के समय जब सड़क संपर्क और सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होती है, तब वैकल्पिक संचार तकनीक राहत एवं बचाव कार्यों में सहायक हो सकती है। हालांकि, इसकी वास्तविक उपयोगिता सेवा की उपलब्धता, लागत, तकनीकी क्षमता और स्थानीय जरूरतों पर निर्भर करेगी। मस्क इसी संभावना को अपने पक्ष में रखते हुए कहते हैं कि स्टारलैंक उन क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचा सकती है, जहां आज भी कनेक्टिविटी की समस्या है। उनका तर्क है कि इससे बच्चों की शिक्षा और छोटे कारोबारों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यह तर्क महत्वहीन नहीं है। लेकिन किसी कंपनी का सामाजिक उपयोगिता का दावा अपने आप में उसके लिए नियामकीय नियमों से छूट का आधार भी नहीं बन सकता। असल सवाल प्रतिस्पर्धा का है। यदि स्टारलैंक भारत में सेवा देना चाहती है, तो उसे निर्धारित सुरक्षा शर्तों और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। दूसरी ओर, सरकार की जिम्मेदारी है कि इन नियमों को सभी पात्र कंपनियों पर समान रूप से लागू किया जाए। किसी कंपनी को केवल इसलिए विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए कि उसका प्रमुख दुनिया का प्रभावशाली उद्योगपति है। इसी तरह, किसी स्थापित भारतीय कारोबारी समूह को भी केवल अपनी बाजार स्थिति के कारण नए प्रतिस्पर्धियों के लिए अनुचित बाधा खड़ी करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने मस्क के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत का उपग्रह संचार संबंधी नियामकीय ढांचा निष्पक्ष और भेदभावरहित है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि भारत किसी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता और सभी कंपनियों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। दूसरी ओर, मस्क को भी यह समझना होगा कि भारत का बाजार केवल संभावित ग्राहकों की बड़ी संख्या का नाम नहीं है। यह अपने कानूनों, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और नियामकीय व्यवस्था वाला संप्रभु देश है। वैश्विक स्तर पर कारोबार करने वाली किसी कंपनी का आकार या प्रभाव उसे भारतीय नियमों से ऊपर नहीं रख सकता। यदि मस्क को किसी प्रक्रिया पर आपत्ति है, तो उसके समर्थन में प्रमाण और नियामकीय तथ्यों को सामने रखना अधिक उपयोगी होगा। किसी भारतीय उद्योगपति पर सार्वजनिक रूप से एकाधिकार का आरोप लगाना अपने आप में उस आरोप को प्रमाणित नहीं करता। मुकेश अंबानी और उनके कारोबारी समूह के संदर्भ में भी यही कसौटी लागू होनी चाहिए। किसी कंपनी की बड़ी बाजार हिस्सेदारी होना और प्रतिस्पर्धा को अनुचित ढंग से रोकना दो अलग बातें हैं। यदि बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित करने वाली किसी गतिविधि के प्रमाण हैं, तो उनकी जांच नियामकीय संस्थाओं को करनी चाहिए। केवल मस्क की टिप्पणी के आधार पर अंबानी पर लगाए गए आरोपों को सही मान लेना उतना ही अनुचित होगा, जितना बिना जांच किसी भी कारोबारी समूह को संदेह से परे मान लेना। इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। भारत में उपग्रह इंटरनेट की प्रतिस्पर्धा केवल स्टारलैंक और रिलायंस जियो के बीच नहीं है। भारती समूह समर्थित यूटेलसैट वनवेब भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी है। ऐसे में नीति का उद्देश्य किसी एक कंपनी को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि ऐसा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाना होना चाहिए जिसमें सभी पात्र कंपनियां समान नियमों के तहत सेवाएं दे सकें। अंततः उपभोक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि मस्क और अंबानी के बीच किसकी कारोबारी ताकत अधिक है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या भारत में इंटरनेट सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, क्या उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलेंगे और क्या प्रतिस्पर्धा के कारण सेवाओं की गुणवत्ता तथा कीमतों में सुधार होगा। दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए तकनीक की सफलता का पैमाना उद्योगपतियों के बीच चलने वाली बयानबाजी नहीं, बल्कि उन्हें मिलने वाली वास्तविक सुविधा है। मस्क का प्राइम मिनिस्टर अंबानी वाला तंज सुखियां बटोर सकता है, लेकिन उससे भारतीय बाजार में एकाधिकार का आरोप सिद्ध नहीं होता। उसी तरह, सरकार का निष्पक्षता का दावा भी पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता। भारत को न तो किसी विदेशी उद्योगपति के दबाव में निर्णय करना चाहिए और न ही किसी घरेलू कारोबारी हित को सार्वजनिक हित से ऊपर रखना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न उद्योगपति सरकार से ऊपर होता है, न कारोबारी प्रतिस्पर्धा के नियम किसी कंपनी की सुविधा के अनुसार तय होने चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून के अनुसार निर्णय करे, नियामकीय प्रक्रिया पारदर्शी रखे और उपभोक्ता के हित को केंद्र में रखे। यही कसौटी तय करेगी कि भारत का डिजिटल भविष्य कुछ कंपनियों के प्रभाव से संचालित होगा या निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और व्यापक जनहित से।

सड़क पर आ गई ‘वोट’ की लड़ाई

कार्यालय संवाददाता
नई दिल्ली/देहरादून। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब सड़कों तक पहुंच गई है। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े छात्र संगठनों के प्रदर्शन ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाताओं के अधिकार और सरकार की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने से यह विवाद और गहरा गया। सवाल अब सिर्फ मतदाता सूची में नाम घटने-बढ़ने का नहीं, बल्कि यह भी है कि लोकतंत्र में मतदाता के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी कौन और किस तरह निभाएगा?

सीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संगठन का कहना है कि मतदाता सूची में सुधार के नाम पर किसी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के जरिए संगठन ने निर्वाचन व्यवस्था की जवाबदेही को सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण कई राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है। विपक्षी दलों की चिंता है कि यदि नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही, तो पात्र मतदाताओं को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, पुनरीक्षण के समर्थकों का तर्क है कि मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को शुद्ध करना आवश्यक है। दोनों पक्षों के दावों के बीच निर्णायक महत्व इस बात का है कि नाम हटाने के कारणों का सत्यापन कैसे हुआ और प्रभावित नागरिकों को अपना नाम वापस जुड़वाने का कितना प्रभावी अवसर मिला।

दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद विवाद का दूसरा मोर्चा

खुल गया। पुलिस ने कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और आवेदन से जुड़ी प्रक्रियागत वजहों का हवाला दिया। वहीं, सीजेपी ने प्रशासन के रुख पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरों ने भी घटनाक्रम को चर्चा में ला दिया। यहां प्रशासन और आंदोलनकारियों, दोनों की भूमिका की कसौटी तय होनी चाहिए। कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी प्रदर्शन पर

◆एसआईआर पर दिल्ली में सियासी टकराव ◆सरकार की जवाबदेही को लेकर नई बहस ◆सीजेपी का प्रदर्शन बन गया बहस का केंद्र ◆मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग

रोक के कारण स्पष्ट और न्यायसंगत होने चाहिए। इसी तरह, लोकतांत्रिक विरोध करने वाले संगठनों से भी अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। विरोध की आवाज और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को मजबूत करता है।

एसआईआर को लेकर जारी विवाद ने राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और क्या प्रत्येक पात्र मतदाता को अपना नाम सूची में बनाए रखने या कटने की स्थिति में उसे दोबारा जुड़वाने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है? इन सवालों का जवाब राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग के आंकड़ों, सत्यापन की प्रक्रिया और शिकायतों के निस्तारण से मिलना चाहिए। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसे बहाल करने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं, यदि किसी नाम को नियमों के तहत

हटाया गया है, तो उसका कारण भी स्पष्ट होना चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही व्यवस्था के दो अनिवार्य पक्ष हैं।

एसआईआर पर विवाद का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि मतदाता सूची चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद है। राजनीतिक दलों के लिए यह केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष निर्वाचन आयोग की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है, जबकि पुनरीक्षण के समर्थक इसे चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन इस बहस में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आम मतदाता है। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि उसका नाम किस राजनीतिक दल के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। उसकी चिंता यह है कि पात्र होने के बावजूद उसका नाम सूची से न कटे और वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। किसी भी राजनीतिक दल को मतदाता के इस अधिकार को अपने आरोप-प्रत्यारोप से छोटा नहीं करना चाहिए।

दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन भले ही एक संगठन की राजनीतिक पहल हो, लेकिन इससे उठे सवाल व्यापक हैं। निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, राजनीतिक दलों को प्रमाणों के आधार पर सवाल उठाने होंगे और प्रशासन को विरोध के अधिकार तथा कानून-व्यवस्था के बीच उचित संतुलन कायम करना होगा। लोकतंत्र की ताकत केवल चुनाव कराने में नहीं, बल्कि इस भरोसे में है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का वोट सुरक्षित है और निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष है। मतदाता सूची पर उठे सवालों का जवाब नारों से नहीं, तथ्यों से देना होगा। क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें बदल सकती हैं, राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप भी बदलते रहते हैं, लेकिन मतदाता के मताधिकार पर जनता का भरोसा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।

अग्रवाल समाज ने महाराजा अग्रसेन का जन्मोत्सव श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया

संवाददाता
देहरादून। अग्रवाल समाज देहरादून द्वारा महाराजा अग्रसेन का जन्मोत्सव अग्रवाल धर्मशाला अग्रवाल भवन गांधी रोड देहरादून में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया।

आज यहां अग्रवाल समाज देहरादून द्वारा महाराजा अग्रसेन का जन्मोत्सव अग्रवाल धर्मशाला अग्रवाल भवन गांधी रोड देहरादून में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया जिसमें अन्य अग्रवाल समाज से जुड़े संगठन भी सम्मिलित रहे।महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के सम्मुखअपने देश व उत्तराखंड प्रदेश की उन्नति सुख समृद्धि व सुख शांति के साथ ही विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। एक ज्योति महाराजा अग्रसेन जी के नाम से लगभग 2100 दीपको की अगर ज्योति प्रज्वलित की गई व माल्यार्पण किया गया। अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल महामंत्री संजय कुमार गर्ग ने अवगत करवाया कि आज सभी अग्र बंधु अग्रवाल धर्मशाला में एकत्र हुए जहां सभी ने

महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा को माल्यार्पण किया इसके पश्चात लगभग 2100 दीपक प्रज्वलित किए गए और सामूहिक आरती की गई इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन जी की जय, कुलदेवी महालक्ष्मी की जय, अग्रोहा धाम की जय के साथ जोरदार जय घोष किया सभी ने उनके दिखाएं आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन जिसमें आम व्यापारियों आदि को लाभ मिल सके। महाराजा अग्रसेन जन्मोत्सव को रचनात्मक दिवस अथवा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। महाराजा अग्रसेन जी की स्मृति में डाक टिकट जारी होना चाहिए।

इस अवसर श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी मंदिर से दिगंबर दिनेश पुरी, विधायक खजान दास, के साथ राज्य मंत्री पुनीत मित्तल, श्याम अग्रवाल, विशाल गुप्ता, पारस गोयल, पार्षद वैभव अग्रवाल, मुकेश सिंघल, सविता कपूर, विनोद चमोली, दिनेश अग्रवाल, पंकज मेसन, सूर्यकांत

धस्माना, लालचंद शर्मा, महापौर सौरव थपलियाल, पूर्व महापौर सुनील उनियाल गामा, राजकुमार आदि ने भी माल्यार्पण कर महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद लिया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल एवं महामंत्री संजय कुमार गर्ग ने कहा कि जनपद देहरादून में अग्रवाल धाम की तर्ज पर जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा हैं जमीन तलाशी जा रही है उन्होंने सरकार से भी इसमें सहयोग करने की मांग उठाई मंदिर के साथ ही आधुनिक चिकित्सालय एवं आधुनिक विद्यालय भी होगा सभी अग्र बंधुओ से इस अभियान में जुड़ने का आग्रह किया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज देहरादून के साथ ही अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, भारतीय वैश्य महासंघ, अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट, उत्तरांचल प्रदेश अग्रवाल महासभा आईवीएफ आदि के पदाधि कारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक खजान दास, अध्यक्ष

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण

अल्मोड़ा (आरएनएस)। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्यालीधार स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, स्टॉन्स रूम की स्थिति तथा ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के रखरखाव से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्टॉन्स रूम की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया और वेयरहाउस में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मशीनों के सुरक्षित भंडारण, रखरखाव तथा उपलब्ध अभिलेखों की जांच की। जिलाधिकारी ने ईवीएम वेयरहाउस से संबंधित विभिन्न पंजिकाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण करते हुए मशीनों के भंडारण और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा तथा अभिलेखों के समुचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का सुरक्षित भंडारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी आवश्यक अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन रखने तथा सुरक्षा संबंधी निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार रवि साह सहित निर्वाचन कार्यालय के कार्मिक उपस्थित रहे।

बरम-कनार सड़क की डीपीआर पूर्ण करने को ज्ञापन सौंपा

पिथौरागढ़ (आरएनएस)। कनार के ग्रामीणों ने बरम-कनार मोटर मार्ग की डीपीआर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शुरू करने की मांग उठाई है। जिला पंचायत सदस्य महेन्द्र सिंह परिहार सहित स्थानीय लोग एकत्र हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग उठाई। कहा कि आजादी के 80 वर्ष बाद भी कनार के लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। कहा क्षेत्र में लगभग 1500 से अधिक की आबादी निवास करती है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के अभाव के कारण गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों व गंभीर मरीजों को डोली के सहारे लगभग 18 किलोमीटर पैदल सड़क तक पहुंचाया जाता है। कहा ग्रामीणों ने पूर्व में अनेक बार आंदोलन व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन-प्रशासन को पत्र भेजकर व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें समस्या से अवगत कराया। जिसके बावजूद अब तक सड़क निर्माण को लेकर डीपीआर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। कहा जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू न होने पर ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ज्ञापन देने वालों में जगत सिंह, उप प्रधान रमेश परिहार, जगदीश बिष्ट, ललित परिहार, उमेश परिहार मौजूद रहे।

खेत में सर्वे करने गई दो महिला उद्यानकर्मियों से अभद्रता

रुद्रपुर (आरएनएस)। ग्राम डोहरा में खेतों में सर्वे करने गई उद्यान विभाग की दो महिला पर्यवेक्षकों को पांच युवकों ने घेर लिया। आरोप है कि युवकों ने दोनों के साथ अभद्रता करते हुए मोबाइल और स्कूटी की चाबी छीने का प्रयास किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उद्यान विभाग की एक महिला पर्यवेक्षक ने बुधवार को कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर वह अपनी महिला सहकर्मी के साथ स्कूटी से ग्राम डोहरा के धान के खेत में सर्वे करने गई थीं। दोनों मोबाइल पर सर्वे का विवरण अपलोड कर रही थीं। इसी दौरान चार युवक खेत में पहुंचे। आरोप है कि सभी नशे में थे और दोनों महिलाओं से अभद्रता करते हुए उनका मोबाइल छीने का प्रयास करने लगे। दोनों ने उन्हें अपने काम और सरकारी आदेश की जानकारी दी, लेकिन आरोपी नहीं माने। महिलाएं किसी तरह खेत से निकलकर सड़क पर खड़ी अपनी स्कूटी के पास पहुंचीं। वहां एक युवक पहले से मौजूद था। दोनों ने स्कूटी से निकलने का प्रयास किया तो पांचों युवकों ने उन्हें घेर लिया और रास्ता रोक दिया। महिलाओं ने विभाग के उद्यान सहायक को फोन कर मौके पर बुलाया। आरोप है कि युवकों ने उद्यान सहायक के साथ भी गाली-गलौज और अभद्रता की। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दोनों महिला पर्यवेक्षक और उद्यान सहायक किसी तरह वहां से निकले। कोतवाली पहुंचकर मामले की सूचना दी गई। एसएसआई जावेद मलिक ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

चुनावी 'बिसात' पर उत्तराखंड में 'नई चाले'

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी तापमान लगातार बढ़ रहा है। भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति को धार देने में जुटी है तो कांग्रेस सरकार को घेरने के साथ अपने संगठन और नेतृत्व के समीकरण साधने की चुनौती से जूझ रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से लेकर बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक यात्राओं तक, हर मुद्दा अब चुनावी चरम से देखा जा रहा है। सियासी मैदान में सवाल सिर्फ सरकार के कामकाज का नहीं, बल्कि विपक्ष की एकजुटता और दोनों दलों की राजनीतिक विश्वसनीयता का भी है।

प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शासन के पक्ष में माहौल बनाए रखने और सत्ता विरोधी असंतोष को सीमित करने की है। पार्टी संगठन बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाया जा रहा है। लेकिन भाजपा के लिए केवल संगठनात्मक मजबूती का दावा पर्याप्त नहीं होगा। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं पर उठते सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता जवाब भी मांगेगी। सरकार के लिए चुनौती यह होगी कि विकास और जनकल्याण के दावों को जमीन पर हुए काम से जोड़कर पेश करे। चुनावी नारों की असली परीक्षा जनता के अनुभवों के बीच ही होगी।

विपक्षी कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। पार्टी बेरोजगारी, पलायन, भर्ती विवाद, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर रही है। मगर इन मुद्दों को चुनावी ताकत में बदलने के लिए कांग्रेस को अपने भीतर के मतभेदों पर भी नियंत्रण रखना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद

विवेचनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए: एसपी सिटी

हल्द्वानी (आरएनएस)। लंबित विवेचनाओं के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर एसपी हल्द्वानी हर्बंस सिंह ने बुधवार शाम सर्किल के विवेचकों की समीक्षा बैठक ली। हल्द्वानी, काठगोदाम, मुखानी और वनभूलपुरा कोतवाली के विवेचक भौतिक रूप से शामिल हुए, वहीं रामनगर, लालकुआं, कालाढूंगी और चोरगलिया क्षेत्र के प्रभारी व विवेचक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में विशेष रूप से 60 और 90 दिन से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई। एसपी सिटी ने संबंधित विवेचकों को साक्ष्यों का समयबद्ध संकलन करने, आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने और विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि विवेचनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कर पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है।



एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर पार्टी नेतृत्व की नाराजगी इसी चुनौती को उजागर करती है। रावत ने पांच अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी तक यात्रा की, जबकि कांग्रेस नेतृत्व ने इसे संगठन से अलग समानांतर कार्यक्रम मानते हुए आपत्ति जताई। बाद में रावत ने प्रस्तावित नौ यात्राएं स्थगित करने की घोषणा की। इस घटनाक्रम ने चुनाव से पहले पार्टी के भीतर नेतृत्व, अनुशासन और राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वह सरकार विरोधी माहौल बनाने के साथ जनता के सामने एक स्पष्ट नेतृत्व, साझा चुनावी कार्यक्रम और भरोसेमंद विकल्प भी प्रस्तुत करे। यदि पार्टी के नेता सार्वजनिक मंचों पर ही अपनी राजनीतिक जगह को लेकर उलझे रहेंगे, तो सरकार के खिलाफ उठाए गए मुद्दों की धार कमजोर पड़ सकती है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने भाजपा और कांग्रेस के बीच एक और मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने मतदाता सूची से नाम कम होने पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा इसे सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया बता रही है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं।

इस विवाद में राजनीतिक बयानबाजी से अधिक महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र मतदाता अपने मताधिकार

से वंचित न रहे। मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान जरूरी है, लेकिन किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हटने पर उसे सुधारने की प्रक्रिया भी सरल और प्रभावी होनी चाहिए। चुनाव से पहले इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता की अहम भूमिका रहेगी।

उत्तराखंड की राजनीति में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता जैसे सवाल चुनावी बहस के केंद्र में रहने वाले हैं। भाजपा अपने शासन और विकास के दावों के साथ जनता के बीच जाएगी, जबकि कांग्रेस सरकार की कमियों को उजागर कर सत्ता परिवर्तन की संभावना तलाशेगी। लेकिन दोनों दलों के सामने एक समान कसौटी है। जनता यह जानना चाहेगी कि रोजगार के कितने अवसर बने, पहाड़ के गांवों में बुनियादी सुविधाएं कितनी सुधरीं, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कितनी बढ़ी और युवाओं का भरोसा जीतने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए। इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक आरोपों से नहीं दिया जा सकता।

उत्तराखंड की सियासत में अभी से आरोपों, यात्राओं, संगठनात्मक बैठकों और राजनीतिक दावों का दौर तेज हो गया है। भाजपा सत्ता बचाने की रणनीति पर काम कर रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए अपने मुद्दों और संगठन को मजबूत करने की कोशिश में है। छोटे दलों और क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों की भूमिका भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल, प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन-सा दल जनता के मुद्दों को विश्वसनीय समाधान में बदल पाता है। भाजपा के लिए शासन के रिकार्ड का हिसाब देना चुनौती है तो कांग्रेस के लिए अपने भीतर एकजुटता और मजबूत विकल्प पेश करना। चुनावी बिसात पर चालें भले अभी से चली जा रही हों, लेकिन अंतिम कसौटी जनता की अपेक्षाएं, नेताओं की जवाबदेही और जमीन पर किए गए काम ही होंगे।

वन्यजीव सप्ताह की प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राएं पुरस्कृत

अल्मोड़ा (आरएनएस)। कनारीछीना वन क्षेत्र के अंतर्गत वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न विद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को वन्यजीव सप्ताह के समापन अवसर पर पुरस्कृत किया गया। वन विभाग की ओर से 5 अक्टूबर को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चमुंवा में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें नितिन सिंह कार्की ने प्रथम, हिमांशु जोशी ने द्वितीय तथा आदित्य सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 6 अक्टूबर को आचार्य नरेंद्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंगलता में निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें अर्जुन भट्ट ने प्रथम, अंजुम नेगी ने द्वितीय तथा भावना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में राजकीय जूनियर हाईस्कूल हरड़ा में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें आरुषी ने प्रथम, भावेश सिंह धानिक ने द्वितीय तथा कल्पना गैड़ा

ने तृतीय स्थान हासिल किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को आयोजित समापन कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में वन क्षेत्राधिकारी कनारीछीना केवलानंद पांडे ने वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में प्रत्येक जीव-जंतु और वनस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विकास के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक वास स्थल प्रभावित हो रहे हैं और जंगलों में भोजन की कमी के चलते वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं।

इस अवसर पर उपराजिक महेश सिंह बोरा, वन दरोगा त्रिलोक सिंह बोरा व भीम सिंह बोरा, वन आरक्षी गौरव, अरविंद प्रसाद आर्या व ज्योति शाही सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।



एसएसपी श्वेता चौबे ने साप्ताहिक परेड का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश

झसंवाददाता

टिहरी। पुलिस बल की शारीरिक दक्षता, अनुशासन एवं कार्यकुशलता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन चंबा के परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड आयोजित की गई। आज यहां जनपद टिहरी गढ़वाल में पुलिस बल की शारीरिक दक्षता, अनुशासन एवं कार्यकुशलता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन चंबा के परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड आयोजित की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे ने स्वयं परेड में प्रतिभाग कर पुलिस अधिकारियों, जवानों एवं प्रशिक्षणरत रिक्‍ट आरक्षियों का उत्साहवर्धन किया। ड्रिल एवं शस्त्र प्रशिक्षण का लिया जायजा, रिक्‍ट आरक्षियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण पर दिया जोर। साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा अनुशासित मार्च, ड्रिल, शस्त्र संचालन एवं शारीरिक दक्षता से संबंधित विभिन्न अभ्यास किए गए। एसएसपी ने जवानों की फूर्ती, कमांड पर प्रतिक्रिया, अनुशासन एवं टीमवर्क का जायजा लेते हुए प्रशिक्षण को निरंतर प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। परेड के पश्चात एसएसपी श्रीमती श्वेता चौबे ने रिक्‍ट प्रशिक्षण केंद्र चंबा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजनालय, प्रशिक्षण कक्ष, बैरक एवं परिसर में उपलब्ध अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से प्रशिक्षणरत रिक्‍ट आरक्षियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परिसर एवं आरटीसी बैरक में साफ-सफाई बनाए रखने, भोजनालय में भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने तथा प्रशिक्षण कक्षों एवं अन्य सुविधाओं को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। साथ ही रिक्‍ट आरक्षियों को बेहतर एवं अनुकूल प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। एसएसपी श्रीमती श्वेता चौबे ने पुलिस लाइन चंबा परिसर में चल रहे मरम्मत कार्यों एवं नवीन निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया।

शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का क्रमिक अनशन जारी

संवाददाता

देहरादून। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार युवा शिक्षा निदेशालय में 113दिन से क्रमिक अनशन पर डटे हुए हैं। आज यहां शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार युवा शिक्षा निदेशालय में 113दिन से क्रमिक अनशन पर डटे हुए हैं। विगत 2006 से लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो आने वाले समय में शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सभी विधायकों सभी मंत्रियों का घेराव शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का 4 जून से शिक्षा निदेशालय ननूरखेडा देहरादून में अनिशिचतकालीन धरने में बैठे हुए हैं प्रशिक्षित बेरोजगार विगत 128दिनों से शिक्षा निदेशालय, ननूरखेडा, देहरादून में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। संगठन का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ रोजी-रोटी की नहीं, बल्कि पहाड़ के सरकारी स्कूलों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करने की भी है। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पाण्डेय ने कहा कि एक तरफ सरकार खेल महोत्सव के जरिए प्रदेश के नौनिहालों की प्रतिभा पर अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया में अपना गुणगान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हकीकत यह है कि प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज तक शारीरिक शिक्षकों के बिना वीरान पड़े हैं। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे अपने दम पर सफलता की कहानी लिख रहे हैं और सरकार उनकी उपलब्धियों पर अपना प्रचार कर रही है। पाण्डेय ने कहा, 128दिन से धरना और 113वा दिन से क्रमिक अनशन चल रहा है, अगर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक तरीके से तेज किया जाएगा।अगर माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी जल्द ही मामला कैबिनेट में नहीं आता है तो प्रशिक्षित बेरोजगार मुख्यमंत्री आवास में आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी।प्रशिक्षित बेरोजगारों की 4 प्रमुख मांगें हैं कि नई शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक से लेकर प्रत्येक इंटरमीडिएट विद्यालय तक एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

कैंचीधाम से विश्व तक: नीम करौली बाबा की आध्यात्मिक विरासत

प्राचीन काल से ही भारत ऋषि-मुनियों, संतो, और मनीषियों की पावन भूमि रहा है। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि दधीचि, महर्षि गौतम, महर्षि अगस्त आदि महान ऋषियों ने भारतीय परंपरा को समृद्ध किया। इसी महान संत परंपरा में 2०वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत बाबा नीम करौली का नाम बड़े सम्मान और आध्यात्मिक श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कोई प्रमाणिक तारीख नहीं है। इतिहास और उनके आधाकारिक दस्तावेज में उनके जन्म का अनुमानित वर्ष 19०० ई. मिलता है।

हिन्दू पचांग के अनुसार उनका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था। इनके पिता दुर्गा प्रसाद तथा माता का नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा नीम करौली का विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। किंतु उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था और वे संन्यासी जीवन की ओर आकर्षित थे। उन्होंने गृह त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया बाद में अपने पिता के आग्रह पर वे पुनः ग्रहस्थ जीवन में लौट आए। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुयीं। बाबा ने मात्र 17 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक ज्ञान की गहन अनुभूति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्ना स्थानों की यात्रा की इसलिए अलग-अलग स्थानों पर लोग उन्हें अलग-अलग नामों से जानते और संबोधित करते थे। गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक हनुमान जी और चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। बाबा नीम करौली कठिन और जटिल उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका दर्शन इतना सरल, सहज और सत्य पर आधारित था कि सामान्य भक्त भी शीघ्र ही उनसे आत्मीय रूप से जुड़ जाते थे। वे अपने भक्तों को सदैव सबकी सेवा करने सबको प्रेम करने भगवान का स्मरण करने और हमेशा सत्य बोलने की प्रेरणा देते थे। वे कहते थे कि भूखों को भोजन कराना और जरूरतमंदों तथा गरीबों की सहायता करना



◆ ललित शर्मा

ही सच्ची पूजा है। उनके लिए मानव सेवा ही ईश्वर का सरल और श्रेष्ठ मार्ग था। बाबा ने अपने जीवन काल में कई दिव्य चमत्कार किए जिसके कारण भक्त उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानने लगे। एक बार कैंची धाम के भंडारे में घी कम पड़ गया था। बाबा के कहने पर नदी का पानी कड़ाही में डाला गया वह अपने आप शुद्ध देशी घी बन गया।

एक बार बाबा को बिना टिकट ट्रेन से उतार दिया गया उनके उतरते ही ट्रेन अचानक रूक गई और काफी प्रयासों के बाद आगे नहीं बढ़ी। अन्ततः बाबा से माफी मांगी गयी और पुनः ट्रेन में बिठाया गया तब जाकर ट्रेन चली। बाबा की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है। ऐसी मान्यता है कि जिन भक्तों के कार्य लंबे समय से नहीं बन रहे हों या जिनकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो, वे यदि सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ नीम करौली बाबा के दर्शन करते हैं, तो बाबा की कृपा से उनकी राह की बाधाएँ दूर होती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त होता है। यही आस्था आज भी असंख्य भक्तों को कैंची धाम की ओर आकर्षित करती है।

एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे वह शांति और मार्गदर्शन की तलाश में भारत आए थे। जब वह कैंचीधाम गये स्टीव जॉब्स ने माना वहां मिली प्रेरणा से स्टीव जॉब्स की जिंदगी और उनके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। जब फेसबुक मुश्किल दौर में थी जब जुकरबर्ग भारत बाबा के आश्रम आये

उन्होंने खुद माना यहां आने के बाद उन्हें अपने लक्ष्य फिर से हासिल करने की नई दिशा और गहरी शांति मिली हॉलीबुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स बाबा से प्रभावित होकर हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुयी। भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली जब खराब फॉर्म के दौर से गुजर रहे थे तब वे बाबा के आश्रम नीम करौली पहुंचे उसके बाद उन्होंने अपनी फॉर्म हासिल कर ली। वैसे तो बाबा नीम करौली से जुड़े भारत सहित विश्व में अनेक आश्रम हैं लेकिन उनके प्रमुख धामों में नैनीताल स्थित कैंची धाम सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा वृन्दावन आश्रम भी बाबा के भक्तों के लिए विशेष आस्था का केन्द्र है। कैंची धाम में हर वर्ष 15 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा के दर्शन करते हैं तथा प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा ने 11 सितम्बर 1973 ई. को अपने नश्वर शरीर त्याग कर महासमाधि ले ली। हाल ही में बाबा की जीवनी पर आधारित बॉलीवुड की एक फिल्म ‘‘ हनुमान अंश ‘ प्रदर्शित हुई। इस फिल्म को दर्शकों का अपार स्नेह और प्यार मिला। फिल्म को देखकर कई दर्शक भावुक हो उठे और बाबा का किरदार निभाने वाले अभिनेता शोभिनव सत्य से गले लगकर रोने लगे। इस फिल्म में शोभिनव सत्य ने बाबा के चरित्र को बेहद प्रभावशाली और भावपूर्ण ढंग से पर्दे पर जीवंत कर दिया।

नीम करौली बाबा का जीवन प्रेम, सेवा, करुणा और मानवता के प्रति समर्पण का संदेश देता है। कैंची धाम से शुरू हुई उनकी आध्यात्मिक विरासत आज भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व के अनेक हिस्सों तक पहुंच चुकी है। उनके भक्तों के लिए बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और सकारात्मक जीवन-दृष्टि के प्रेरणास्त्रोत हैं। समय बीतने के साथ उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बाबा की शिक्षाएँ और आध्यात्मिक विरासत आने वाली पीढ़ियों को भी मानव सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी।

शब्द सामर्थ्य -050

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. जीत, फतेह 3. राशन सामान बेचने वाली एक जाति, वैश्य 6. मुर्गी की जाति की एक पक्षी, आधा... आधा बटेर 7. कमल, पंकज, भारत के एक दिवंगत प्रधानमंत्री का नाम 8. नहाने का स्थान, स्नानागार 10. ख्वाब, स्वप्न 12. बुलावा, निमंत्रण 14.

तबाही, बर्बादी 17. कत्ल, वध 18. क्षतिपूर्ति, सुआवजा 19. करार, चैन, आराम 21. दृष्टि, निगाह 23. नाश करने योग्य 24. लाडला, प्यारा 25. सीताजी, जनकनंदनी।

ऊपर से नीचे

1. शादी, ब्याह 2. अनाथ, निराश्रित 3. साल, वर्ष 4.

दोस्ताना, यारी 5. सुर, देव, भगवान 9. मनुष्य, इंसान, आदमी 11. पाटा जाना, चुकता करना, बात तय करना 12. कार्यक्षेत्र, गोल घेरा, वृत्त 13. अधीनता, मातहती, अधिकार 15. नगर 16. गैरजरूरी 20. दृष्टांत, सुपुर्दगी, उदाहरण 22. धरती, भूतल, धरातल।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 49 का हल

अं	त	म	री	ज			
ग	ह	न	ता	ब	र	ब	स
	की		धि	क्का	र		र मा
	का		का		द	वा	खा ना
प	त	वा	र		स्त	र	
ह						दा	मि नी
ना		ए	ह	ति	या	त	लां
वा	च	क		हा		खू	ब
			ता	ब	ड़	तो	ड़ र



सोनाली बेद्रे की मराठी फिल्म सोहला का ट्रेलर जारी, 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री सोनाली बेद्रे अब मराठी सिनेमा में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। उनकी पहली मराठी फिल्म 'सोहला' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। पारिवारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों पर आधारित यह फिल्म 13 वर्षीय लड़के की कहानी के माध्यम से बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ने की भावनात्मक यात्रा को सामने लाती है।

'सोहला' एक पारिवारिक नाटक है, जिसकी कहानी 'पश्या' नाम के 13 वर्षीय लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है। महाराष्ट्र की एक पारंपरिक प्रथा के अनुसार, जब लड़का 13 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो उसके लिए एक विशेष पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है, जिसे 'सोहला' कहा जाता है। इसे बचपन से बड़े होने की दिशा में उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाता है।

फिल्म इसी परंपरा की पृष्ठभूमि में एक परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह अचानक सामने आए पारिवारिक संकट बच्चों को समय से पहले जिम्मेदार और समझदार बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। 13 वर्षीय पश्या भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरता है, जहां उसे बचपन की सहज दुनिया से निकलकर परिवार की जिम्मेदारियों को समझना पड़ता है।

फिल्म में पारिवारिक भावनाओं, रिश्तों और बदलती परिस्थितियों के बीच एक बच्चे के मानसिक और भावनात्मक बदलाव को प्रमुखता दी गई है। ट्रेलर से संकेत मिलता है कि कहानी केवल एक पारंपरिक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से परिवार, जिम्मेदारी और बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

'सोहला' को सोनाली बेद्रे प्रस्तुत कर रही हैं, जबकि उनके पति गोल्डी बहल इसके निर्माता हैं। फिल्म का निर्माण सचिन श्रीवास्तव, रत्ना श्रीवास्तव और कविता बागवान ने रोज ऑडियो विजुअल्स और कैरियन फिल्मस के सहयोग से किया है। फिल्म का निर्देशन सैकत बागवान ने किया है।

मराठी सिनेमा में सोनाली बेद्रे की यह पहली फिल्म है। लंबे समय से हिंदी फिल्मों में सक्रिय रही अभिनेत्री के प्रशंसकों के बीच भी इस फिल्म को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। पारिवारिक कहानी और मराठी संस्कृति से जुड़ी पृष्ठभूमि के कारण 'सोहला' को एक अलग विषय वाली फिल्म के रूप में देखा जा रहा है।

'सोहला' 16 अक्टूबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। फिल्म के ट्रेलर के जारी होने के साथ ही इसकी कहानी और कलाकारों को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ गई है।

नई नवेली' का नया गाना फटा पटाखा' जारी, जॉम्बी संग थिरकती नजर आई यामी गौतम

अभिनेत्री यामी गौतम की आगामी फिल्म 'नई नवेली' दशहरा के अवसर पर दर्शकों के मनोरंजन के लिए सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसमें यामी गौतम को एक अलग और अनोखे किरदार में देखा गया है। अब निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना 'फटा पटाखा' जारी कर दिया है, जो अपनी ऊर्जावान धुन और धमाकेदार नृत्य के कारण चर्चा में है।

गाने के वीडियो में यामी गौतम एक अनोखी दुनिया में जॉम्बी के साथ नृत्य करती नजर आ रही हैं। गाने की प्रस्तुति में तेज संगीत, नृत्य और मनोरंजन का भरपूर मिश्रण देखने को मिलता है। यामी का जॉम्बी के साथ किया गया नृत्य इस गाने का खास आकर्षण है। इसकी ऊर्जावान धुन श्रोताओं को झूमने पर मजबूर करती है।

जी म्यूजिक कंपनी ने अमेजन, एमजीएम स्टूडियोज और कलर येलो के सहयोग से यह गाना प्रस्तुत किया है। 'फटा पटाखा' को मधुबंती बागची ने अपनी आवाज दी है। गाने का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, जबकि इसके बोल वायु ने लिखे हैं।

गाने के वीडियो में जॉम्बी की एक अलग दुनिया को दर्शाया गया है। इसी पृष्ठभूमि में यामी गौतम का नृत्य फिल्म के मनोरंजक और रहस्यमय अंदाज की झलक देता है।

बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी 'नई नवेली' को मनोरंजक पारिवारिक फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म में हास्य के साथ रहस्य और रोमांच का भी मिश्रण देखने को मिलेगा। निर्माताओं ने इसके ट्रेलर के जरिए यामी गौतम के अब तक के अलग अंदाज की झलक दिखाई है।

फिल्म 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दशहरा के आसपास रिलीज होने के कारण निर्माताओं को पारिवारिक दर्शकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद है।

अनुपमा के साथ दो साल पूरे करना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, इशिता दीक्षित ने साझा किए अनुभव

धारावाहिक अनुपमा में पिछले दो साल से परी का किरदार निभा रहीं अभिनेत्री इशिता दीक्षित ने कहा कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और खास पल है। इशिता ने कहा, अनुपमा जैसे बड़े शो के साथ दो साल पूरे करना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और एक अहम माइलस्टोन है। मैं बहुत शुक्रगुजार और खुश हूं। राजन शाही सर की हमेशा आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया, क्योंकि अनुपमा के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और यही सच है। इशिता ने कहा कि जब उन्होंने परी का किरदार निभाना शुरू किया था, तब वह बहुत अलग थी और अब वह लड़की बहुत बदल गई है।

इशिता ने कहा, इस सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। दो सालों में मैंने जो ग्रोथ दिखाई है, उससे मैं सच में खुश हूं। आज मैं बिल्कुल अलग महसूस करती हूं, न सिर्फ परी के तौर पर, बल्कि अपनी कला और एक एक्टर के तौर पर भी मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं और जब आप सेट पर इतने सारे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो आप उन्हें देखकर, उनके काम करने के तरीके को समझकर और उनके साथ सीन करके लगातार सीखते रहते हैं।

इशिता ने बताया, यह मेरे लिए बहुत शानदार अनुभव रहा है और मुझे उम्मीद है कि यह ऐसे ही चलता रहेगा। देखते हैं कि परी और मैं कब तक साथ रहते हैं, लेकिन सच कहूं तो, मैं चाहूंगी कि यह सफर लंबा चले क्योंकि मैं अधिक से अधिक समय तक परी का किरदार निभाना चाहती हूं।

इशिता ने कहा, अब तक, वह (परी)



मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जब आप इतने सालों तक कोई किरदार निभाते हैं, तो कभी-कभी आप भूल जाते हैं कि असल जिंदगी क्या है और रील लाइफ क्या। पहले, हर इंटरव्यू में मैं कहती थी कि परी और मुझमें कोई समानता नहीं है। लेकिन दो साल बाद, मुझे लगता है कि हममें काफी समानताएं आ गई हैं।

एक्ट्रेस ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, कहीं न कहीं, मेरे असली रूप और परी के बीच का फर्क मिटने लगा है क्योंकि मैं इतने लंबे समय से उसके साथ रही हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वह करती है या जिन भावनाओं से वह गुजरती है, उन्हें देखकर अब मुझे लगता है, शायद मैं भी थोड़ी-बहुत परी जैसी हूं।

रावी गुप्ता ने बताया कैसे बदल गई टीवी इंडस्ट्री!



अभिनेत्री रावी गुप्ता इन दिनों लोकप्रिय सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के दूसरे सीजन में दामिनी (गौतम विरानी की पत्नी) के किरदार में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि पहले की तुलना में आज काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी है और मुझे लगता है कि आगे भी बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में बदलाव आगे भी

जारी रहेगा, खासकर तकनीक के मामले में। अगर मैं क्योंकि सास भी बहू की तुलना-2 की तुलना पहले शो से करूं, तो दोनों की तकनीक में जमीन-आसमान का फर्क है।

अभिनेत्री ने अपने किरदार पर बात करते हुए कहा, मेरा किरदार खुद ही एक सरप्राइज है। लोगों को लगा था कि दामिनी निगेटिव होगी, क्योंकि पिछले सीजन में मैंने निगेटिव रोल किया था। सबको लगा

कि वह कुछ गलत करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में वह एक आम औरत है, जिसकी अपनी परेशानियां हैं। वह ज्यादा ड्रामा नहीं करती और यही इस किरदार को खास बनाती है।

अभिनेत्री ने बताया कि पहले के मुकाबले अब उन्हें डेली सोप में बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, पहले के समय में निगेटिव रोल को बिल्कुल बुरा ही दिखाते थे, जैसे कि उनमें कुछ अच्छा है ही नहीं और उनकी हर चीज को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता था। खासकर महिलाओं के मामले में, अगर किरदार पॉजिटिव है, तो उसे देवी बना दिया जाता था, लेकिन अब मुझे बदलाव नजर आ रहा है। डेली सोप में भी अब किरदारों में गहराई देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा बदलाव है।

उन्होंने आगे कहा, एक समय था जब डेली सोप को लेकर सोच बन गई थी कि महिलाओं को हमेशा दबा हुआ दिखाया जाता था। उन्हें तभी अच्छा माना जाता था, जब वह परिवार के लिए कुर्बानी दें। असल, जीवन में इस तरह का दिखावा महिलाओं को पीछे धकेल सकता है। अब मैं देख रही हूं कि किरदार कैसे बदल रहे हैं। अब डेली सोप में महिलाओं को घरेलू हिंसा और मैरिटल रेप जैसे मुद्दों पर बात हो रही है, जो कि बहुत जरूरी है और ऐसे मुद्दे समाज में बहुत बड़ा असर भी छोड़ रहे हैं।

शिविर में ग्रामीण पहुंचे, जिम्मेदार अधिकारी पहुंचना भूले

नई टिहरी(आरएनएस)। यमुना नदी पर प्रस्तावित 3०० मेगावाट लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित काश्तकारों के भूमि अभिलेखों के सत्यापन के लिए बृहस्पतिवार को नैनबाग तहसील में लगाया गया शिविर अधिकारियों के नहीं पहुंचने से खानापूर्ति साबित हुआ। दस्तावेज लेकर शिविर में पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि तहसील प्रशासन और यूजेवीएनएल के जिम्मेदार अधिकारी शिविर में नहीं पहुंचे जिससे वे अपनी समस्याएं और मुआवजे से जुड़े मामले अधिकारियों के सामने नहीं रख पाए। ग्रामीणों ने शिविर को महज खानापूर्ति बताते हुए रोष जताया। लखवाड़ परियोजना के लिए अर्जित भूमि से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन के लिए मरोड़, मेलगढ़, टटोर, खरसोन, खैराड़ और धिलिडचक गांवों के काश्तकार नैनबाग तहसील सभागार पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि शिविर में प्रशासन और यूजेवीएनएल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। भूमि व परिसंपत्तियों से जुड़े लंबित मामलों पर बात होगी लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के नहीं पहुंचने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीण शरण सिंह पंवार, विक्रम कैतुरा, देशपाल पंवार, कैलाश बिजल्वाण, गंभीर सिंह रावत ने आरोप लगाया कि प्रशासन प्रभावित काश्तकारों से बार-बार भूमि के दस्तावेज और शपथपत्र मांग रहा है जबकि उनकी भूमि से संबंधित अभिलेख तहसील में पहले से मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जमा कराने के बावजूद परिसंपत्तियों के मुआवजे और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।

ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में भी कई बार प्रभावितों से दस्तावेज मांगे जा चुके हैं। इसके बावजूद शिविर में अधिकारियों के नहीं पहुंचने से वे अपनी बात रखने से वंचित रह गए। यूजेवीएनएल की ओर से कुछ कर्मचारी शिविर में पहुंचे लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की गैरमौजूदगी में शिविर केवल औपचारिकता बनकर रह गया। शिविर में मिजान सिंह रावत, अर्जुन रावत, बचन सिंह रावत, सरदार सिंह रावत, विक्रम कैतुरा, पीतांबर दत्त, प्रदीप, मयंक बिजल्वाण, कैलाश, गोपाल दत्त, सवया देवी, राजेंद्र नौटियाल आदि मौजूद रहे।

तहसील में कई अधिकारियों के पद रिक्त

चमोली(आरएनएस)। तहसील नारायणबगड़ में तहसीलदार समेत अन्य रिक्त पदों को भरने की मांग के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव ने उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजा। बताया गया कि नारायणबगड़ विकासखंड में 79 ग्राम पंचायतें हैं लेकिन तहसील में तहसीलदार समेत अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर कर्मियों की नियुक्ति न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव संदीप कुमार पटवाल ने एसडीएम यशवीर सिंह के माध्यम से ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि 3० सितंबर को तहसीलदार की सेवानिवृत्ति हो जाने एवं कनिष्ठ सहायक समेत अन्य कई पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने से लोगों को कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

सू- दोकू क्र.050								
	7				1		3	
1		9				5		
			3				1	
		5						3
3					2		5	
				3				2
	4						7	
7		8		1		6		
	6		7		9			1

नियम 1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है। 2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है। 3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।	सू-दोकू क्र.49 का हल								
	5	2	4	9	6	7	8	1	3
	3	6	7	4	1	8	2	9	5
	8	1	9	3	2	5	4	6	7
	6	3	5	1	9	4	7	2	8
	7	9	8	5	3	2	6	4	1
	2	4	1	7	8	6	5	3	9
	4	5	3	6	7	9	1	8	2
	9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6	

कुंजापुरी मेले की स्वर्ण जयंती धूमधाम से मनेगी: पंवार

नई टिहरी(आरएनएस)। सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के स्वर्ण जयंती महोत्सव को यादगार बनाने के लिए नगर पालिका तैयारियों में जुटी है।

नौ दिनों तक होने वाले मेले के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। 11 अक्तूबर को अपराह्न 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मेला समिति अध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार ने बताया कि प्रथम सांस्कृतिक संध्या में पद्मश्री डॉ. बसंती बिष्ट, लोक गायिका संगीता ढौंडियाल, मीना राणा और किशन महिपाल प्रस्तुति देंगे। दूसरे दिन खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ होगा। मार्चपास्ट के साथ राष्ट्रीय

आईटीआई फलसीमा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

अल्मोड़ा (आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा के अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह की ओर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलसीमा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन लैंगिक समानता के विषय पर किया गया। शिविर का शुभारंभ नालसा के थीम गीत एक मुट्ठी आसमान के साथ हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों को लैंगिक न्याय, ट्रांसजेंडर अधिकार, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम 2०12 सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। महिला थाना एनटीडी की उपनिरीक्षक बीना पपोला ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार और साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए जानकारी प्रदान की। शिविर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य जग प्रीतम टम्टा और अधिकार मित्र मौजूद रहे।

स्तर की महिला और पुरुष ओपन वॉलीबाल प्रतियोगिता शुरू होगी। 13 अक्तूबर को बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता होगी।

रात आठ बजे आंचल विद्या भारती, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल और कृष ज्योति विद्यालय समेत विभिन्न संस्थानों के कार्यक्रम होंगे। चौथे दिन कैरम और शतरंज प्रतियोगिता होगी। रात आठ बजे हास्य कलाकार सुदेश लहरी और राजीव ठाकुर स्टेज शो करेंगे। रात 1० बजे अजय चौहान, अजय तोमर एंड पार्टी की प्रस्तुति होगी। 15 अक्तूबर को आर्मी खेल मैदान में महिला-पुरुष ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू होगी। रात नौ बजे गढ़वाल के पांडव बैंड की प्रस्तुति होगी। 16 अक्तूबर को बेबी शो और कला-भाषण प्रतियोगिता होगी।

रैम्प वॉक में छात्राओं ने बिखेरा जलवा, विजयलक्ष्मी बनीं मिस फेशर

हरिद्वार(आरएनएस)। महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, सतीकुंड कनखल में नवागत छात्राओं के स्वागत समारोह में रैम्प वॉक आकर्षण का केंद्र रहा। बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं ने रैम्प पर आत्मविश्वास और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न चरणों के बाद विजयलक्ष्मी को मिस फेशर चुना गया। निहारिका फर्स्ट रनरअप और रिया शर्मा सेकेंड रनरअप रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की सचिव डॉ. वीणा शास्त्री ने किया। उन्होंने नवागत छात्राओं का स्वागत करते हुए कहा कि जीवन को उत्साह और जीवटता के साथ जीते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने छात्राओं से निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया।श्रीशीशराम मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव डॉ. अशोक शास्त्री ने कहा कि छात्राओं को अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाते हुए अलग पहचान बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्राएं देश का भविष्य हैं और उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। प्राचार्या प्रो. शशी प्रभा ने प्रथम वर्ष की छात्राओं का स्वागत करते हुए कहा कि महाविद्यालय में शिक्षा के साथ मिलने वाला अनुभव उनके व्यक्तित्व को नई दिशा देगा। उन्होंने सफल आयोजन के लिए छात्राओं को बधाई दी। समारोह में तृतीय और पंचम सेमेस्टर की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरीं। छात्र संघ समिति की डॉ. राखी सिंह और डॉ. निभा राठी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

जनभागीदारी से हारेगा, टीबी मुक्त बनेगा भारत

नई टिहरी(आरएनएस)। जिला मुख्यालय से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने जोश टीम को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न विकासखंडों के लिए रवाना किया। इससे पूर्व विकास भवन में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सजीव संबोधन को सुना।कार्यक्रम में विधायक राजकुमार पोरी ने उपचाराधीन क्षय रोगियों को पोषण किट वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों, एनसीसी कैडेट्स, माय भारत वॉलंटियर्स आदि को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई। सीएमओ डॉ. मेघना असवाल ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए समय पर जांच, नियमित उपचार और जन-जागरूकता जरूरी है। जनपद में विकासखंडवार 15 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। प्रत्येक नोडल अधिकारी के साथ पांच- पांच एनसीसी कैडेट व माय भारत वॉलंटियर्स को भी शामिल किया गया है। इस मौके पर डॉ. श्वेता नवानी, डॉ. सुरेंद्र सिंह, डॉ. अलीशा, चीफ फार्मासिस्ट जेपी टम्टा आदि मौजूद रहे।

एचटीसी की बैठक में सुरक्षित रक्त सेवाओं के सुचारु संचालन पर हुआ मंथन

अल्मोड़ा(आरएनएस)। सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान से संबद्ध गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय में नवगठित हॉस्पिटल ट्रांसफ्यूजन कमेटी की पहली बैठक ओपीडी बाल रोग विभाग के सभागार में आयोजित हुई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राज्य रक्त आधान परिषद, उत्तराखंड के दिशा-निर्देशों के क्रम में आयोजित बैठक में अस्पताल में सुरक्षित रक्त आधान और ब्लड बैंक की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई।

प्राचार्य प्रो. गोविंद सिंह तितियाल के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति के चेयरमैन एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉ. डीसी पुनेरा ने की।

समिति के संयोजक सचिव एवं नोडल अधिकारी तथा प्रभारी रक्त केंद्र डॉ. आशीष जैन की अगुवाई में रक्त एवं उसके घटकों की उपलब्धता, गुणवत्ता तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में निश्चेतक विभागाध्यक्ष डॉ. उर्मिला पलड़िया, पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष एवं क्लीनिकल हीमेटोलॉजिस्ट डॉ. अंकित कौशिक, मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार, सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश सिंह चौहान, ऑर्थोपेडिक विभागाध्यक्ष डॉ. शुजा नाजिम, इमरजेंसी विभाग के मेडिकल ऑफिसर डॉ. नीलेश एवं डॉ. किरन, गायनी विभाग की सह प्राध्यापक डॉ. श्वेता एवं

शाम 8 बजे से ग्रियंका मेहरा एंड पार्टी और हेमा नेगी करासी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगी। 17 अक्तूबर को मुख्य बाजार से ड्रग्स फ्री हाफ मैराथन शुरू होगी। रात 9 बजे से गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी एंड पार्टी और डांस स्टार दीक्षा बडोनी एंड पार्टी प्रस्तुति देंगे। 18 अक्तूबर को फैंसी ड्रेस, चम्मच दौड़, बोरा दौड़, म्यूजिकल चेयर और रस्साकसी की प्रतियोगिताएं होंगी। सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा प्रस्तुति देंगी।

मेले के अंतिम दिन 19 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे समापन समारोह शुरू होगा। इस दौरान जय मां कुंजापुरी लकी ड्रॉ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में गायक प्रीतम डॉ. प्रीतम भरतवाण प्रस्तुति देंगे।

डॉ. मेघा, बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अमित कुमार सिंह एवं डॉ. नौशीन, रेडिएशन थेरेपी प्रभारी डॉ. अंकुर यादव, ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. भावना पंत और दंत रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल पांडे, उप नर्सिंग अधीक्षिका लीला बिष्ट एवं पुष्पा राजवंश, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हेम चंद्र बहुगुणा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में सभी सदस्यों ने रक्त केंद्र की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ बनाने तथा मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर सहमति जताई। स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक सहभागिता के साथ गैर सरकारी संगठनों की मदद लेने पर भी जोर दिया गया।

प्रमाण पत्र निर्गत न होने से आमजन को हो रही परेशानी: रघुनाथ सिंह नेगी

संवाददाता

देहरादून। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रमाण पत्र निर्गत न होने से आमजन को परेशानी हो रही है।

आज यहां जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जनपद देहरादून की समस्त तहसीलों में उप राजस्व निरीक्षकों (लेखपालों) द्वारा आय/निवास/जाति आदि प्रमाण पत्र बनाने का कार्य बहिष्कार किये जाने की वजह से आमजन को काफी परेशानी हो रही है। उक्त प्रमाण पत्र न बनने के कारण कई युवाओं के रोजगार संबंधी आवेदन पत्रों में प्रमाण पत्र न लगने की वजह से निर्धारित तिथि निकली जा रही है तथा कई लोगों को सरकार की योजनाओं आदि का लाभ लेने के लिए लगने वाले आय/निवास/हैसियत आदि प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण भी आवेदन पत्र नहीं भरे जा रहे हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि तत्काल लेखपालों की मांगों पर गौर कर जनता को न्याय दिलाने का काम करे। नेगी ने कहा कि अगर कोई मामला शासन स्तर से हल होना है तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा व दिलबाग सिंह मौजूद थे।



हुड़दंग करने वाले तीन गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पटेलनगर पर सूचना प्राप्त हुई की पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत नयागांव क्षेत्र मे दो पक्षों के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग किया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर कोतवाली पटेलनगर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा कर रहे व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया गया, पर उक्त व्यक्ति पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने तथा और अधिक उग्र होकर आपस मे मारपीट पर उतारू हो गये, मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत पुलिस द्वारा झगड़ा कर रहे 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम मोहम्मद अफजल पुत्र अनवर हुसैन निवासी परवल उम्मेदपुर कोतवाली पटेलनगर, इकबाल पुत्र बुन्दु निवासी परवल उम्मेदपुर कोतवाली पटेलनगर, अलीशेर पुत्र बिन्दु हसन निवासी सिंगनीवाला सहसपुर बताया।

प्रधानाचार्य को धमकी देने के मामले में तीन लोग हिरासत में

हमारे संवाददाता

नैनीताल। डिग्री कॉलेज रामनगर के प्रधानाचार्य को जान से मारने की धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मामले में नामजद तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार, आठ अक्टूबर को डिग्री कॉलेज रामनगर में शासन के निर्देश पर 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित किया जाना था। कार्यक्रम में जिलाधि कारी नैनीताल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी प्रस्तावित थी। इसका उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का मौके पर निस्तारण करना था।

कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस के मुताबिक, वीडियो में तीन युवक पूर्व छात्रसंघ चुनाव से जुड़े विषय पर चर्चा करते सुनाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान कथित तौर पर प्रधानाचार्य को आग लगाने की धमकी देने संबंधी टिप्पणी भी की गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया।

प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में रामनगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जिन तीन युवकों को नामजद किया है, उनमें मो. अनस (21), निवासी शक्तिनगर पूछड़ी, रामनगर; कपिल बिष्ट (26), निवासी किशनपुर छोई, रामनगर; और सानिब सिद्दीकी (24), निवासी टांडा, रामनगर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस की कार्रवाई का आधार सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो और उसमें कथित तौर पर दी गई धमकी है।

अग्रवाल समाज ने महाराजा अग्रसेन..

◀ पृष्ठ 2 का शेष

कमलेश अग्रवाल, महामंत्री संजय कुमार गर्ग सुनील अग्रवाल, कपिल गुप्ता, सुरेश बाबा, योगेश अग्रवाल, रोशन अग्रवाल, आनंद गर्ग, सतीश कंसल, अमित गोयल, निर्मल गोयल, अनामिका जिंदल, नूपुर गुप्ता, रुचि गुप्ता, मोनिका, दीपक गर्ग अंकुश अग्रवाल, हरीश मित्तल, श्याम सुंदर गोयल, रीना सिंघल, एमसी गुप्ता, आरसी गर्ग, अमरकांत गर्ग, अमित गुप्ता, अजय गर्ग, घनश्याम अग्रवाल, नवीन गुप्ता, विक्की गोयल, अजय गोयल, हर्ष अग्रवाल, महेश गुप्ता, विवेक अग्रवाल, दिवाकर अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनोज सिंघल, दीपक शरण अग्रवाल, कान्हा मित्तल आदि उपस्थित रहे।

शीतकाल के लिए बंद हुए श्री हेमकुण्ड साहिब के कपाट

हमारे संवाददाता

चमोली। हिमालय की गोद में लगभग 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित 'सिखों' के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुण्ड साहिब एवं पौराणिक श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सेना के बैंड की मधुर धुनों, शबद-कीर्तन और अंतिम अरदास के बीच माहौल भावुक हो उठा। आस्था, सेवा और समर्पण के इस अद्भुत संगम के साथ इस वर्ष की यात्रा का समापन हुआ।

23 मई से शुरू हुई श्री हेमकुण्ड साहिब की यात्रा में 'इस वर्ष 3,84,573 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र धाम में मत्था टेका।' कपाट बंद होने के पावन अवसर पर गोविंद धाम (घांघरिया) से रागी जत्थे सहित हजारों श्रद्धालु हेमकुण्ड साहिब पहुंचे। इनमें पाकिस्तान से आया 40 सदस्यीय सिख श्रद्धालुओं का जत्था भी शामिल रहा। खुशनुमा मौसम और बर्फ से ढकी सप्तश्रृंग घाटी के मनमोहक नजारों के बीच श्रद्धालु आध्यात्मिक



वातावरण में लीन नजर आए।

कपाट बंद होने के अवसर पर प्रातः सुखमणी साहिब के पाठ से धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। सुबह शबद-कीर्तन हुआ और दोपहर यात्रा की अंतिम अरदास की गई। इसके पश्चात हुक्मनामा लेकर गुरु ग्रंथ साहिब को पंज प्यारों की अगुवाई में सेना के बैंड की मधुर एवं गौरवशाली धुनों के बीच दीवान हॉल से सचखंड साहिब में सुशोभित किया गया। अंततः श्री हेमकुण्ड साहिब एवं श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए।

इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे

श्रद्धालुओं के बीच मौसम की चुनौतियां भी कम नहीं रहीं। भारी बर्फबारी, बारिश, कड़ाके की ठंड और फिसलन भरे दुर्गम रास्तों के बावजूद पुलिस और 'क्वै' के जवान लगातार मुस्तेदी से डटे रहे। 'पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार' के कुशल नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवाजाही और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सतत निगरानी रखी गई। कठिन रास्तों पर जवानों ने श्रद्धालुओं का हाथ थामकर उन्हें सुरक्षित रास्ता पार कराया और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई।

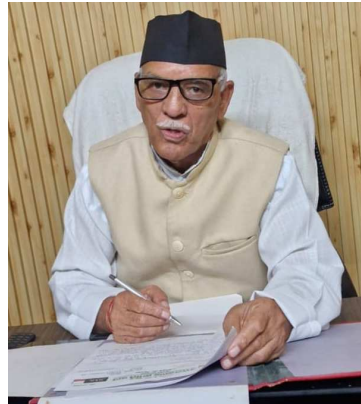
गुरुद्वारा 'श्री हेमकुण्ड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिन्दा' एवं 'वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह' ने यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, मुस्तेदी और कुशल प्रबंधन के लिए 'प्रभारी निरीक्षक गोविन्दघाट चित्रगुप्त सिंह तथा चौकी प्रभारी घांघरिया अमनदीप सिंह' की विशेष रूप से सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

11 से 17 अक्टूबर तक निकलेगी उत्तराखंड उत्थान यात्रा: कुकरेती

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखण्ड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र कुकरेती ने कहा कि 11 से 17 अक्टूबर तक उत्तराखण्ड उत्थान यात्रा निकाली जायेगी।

आज यहां उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र कुकरेती ने प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य, जन अधिकारों और क्षेत्रीय अस्मिता की रक्षा के संकल्प के साथ 11 से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 'उत्तराखंड उत्थान यात्रा' में समस्त प्रदेशवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उत्तराखंड के स्वाभिमान, जनभावनाओं, युवाओं के भविष्य और प्रदेश के वास्तविक विकास के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। हल्द्वानी से प्रारंभ होकर कुमाऊँ मंडल की सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने वाली इस यात्रा का उद्देश्य जनता के



बीच जाकर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है। केंद्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश के युवाओं, मातृशक्ति, राज्य आंदोलनकारियों, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों तथा उत्तराखंड के हितों के लिए कार्य कर रहे सभी नागरिकों से इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना जिन सपनों, संघर्षों और बलिदानों

के आधार पर हुई थी, उन्हें साकार करने के लिए प्रदेश की जनता को एकजुट होकर आगे आना होगा। आज आवश्यकता है कि उत्तराखंड के संसाधनों पर प्रदेशवासियों के अधिकार, युवाओं के लिए रोजगार, पलायन पर प्रभावी रोक, मूल निवास एवं भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जनजागरण को व्यापक बनाया जाए। कुकरेती ने कहा, "आइए, हम सब मिलकर उत्तराखंड उत्थान यात्रा को जन-जन का अभियान बनाएं। यह हमारी अस्मिता, हमारे अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। एकजुट होकर ही हम समृद्ध, स्वाभिमानी और सशक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर सकते हैं। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बनें और उत्तराखंड के हितों की रक्षा तथा प्रदेश के बेहतर भविष्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर ध्यान सत्र का आयोजन: रविशंकर

संवाददाता

देहरादून। गुरुदेव रविशंकर ने बताया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ध्यान सत्र का आयोजन किया गया।

आज यहां परेड ग्राउंड स्थित एक क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गुरुदेव रविशंकर ने बताया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिव के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा एक घंटे का विशेष ध्यान एवं मानसिंह स्वास्थ्य सत्र का आयोजन किया गया है। उन्होंने तैमान में मानसिंह स्वास्थ्य की बढ़ती आवश्यकता और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि आज की व्यस्त और अनिश्चितकता से भी जीवनशैली में ध्यान न तो फैशन है और न ही विलासिता, बल्कि संमय की आवश्यकता है। सूचनाओं की निरंतर बढ़ती मात्रा,



कार्य का दबाव, अकेलापन शांति का अनुभव करने के लिए नियमित रूप से समय निकालना आवश्यक है। ध्यान व्यक्ति को अधिक शांति, सजग, एकाग्र और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाने में सहायक हो सकता है।

उन्होंने प्रतिदिन सुबह और शाम 15 से 20 मिनट ध्यान के लिए निकालने पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार हम शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं उसकी प्रकार मन की शान्ति और

स्वच्छता के लिए समय देना चाहिए। स्वस्थ मन अच्छी नींदनी, सकारात्मक दृष्टिकोण और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में क्षमता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजबूत मन कमजोर शरीर को भी सम्भाल सकता है। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के मीडिया कोआर्डिनेटर संजय भार्गव, सुश्री नंदिता सिंह, आनंद कंसल, ललित माहेन, ऋषभ कोहली व अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: एसआईटी ने दाखिल की 1000 पन्नों की चार्जशीट



◆मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी

हमारे संवाददाता चमोली। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच पूरी होने के बाद पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने न्यायालय में करीब एक हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। 50 गवाहों पर आधारित इस आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों के खिलाफ वाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई

22 अक्टूबर को होगी। ज्योतिर्मठ स्थित न्यायालय में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर ने आरोपपत्र और संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसके बाद तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता पाए जाने पर संज्ञान लिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मंदिर

में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और भेंट सामग्री की गणना कर उसे नियमानुसार मंदिर समिति के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की निगरानी में थी। राजेंद्र सिंह चौहान ने कथित तौर पर आपसी षड्यंत्र के तहत दान की रकम और भेंट सामग्री के एक हिस्से का गबन किया। वहीं, सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार पर दान की थाली से प्राप्त भेंट सामग्री चोरी करने का आरोप है।

अभियोजन के मुताबिक, उसके कब्जे से कथित तौर पर चोरी की गई सामग्री और उसे बेचने से मिली रकम भी बरामद की गई थी। मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान वर्तमान में जिला कारागार पुरसाड़ी में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। न्यायालय ने दोनों के संबंध में न्यायिक अभिरक्षा के वारंट जारी किए हैं। वहीं, जमानत पर चल रहे तीसरे आरोपी मनोज कुमार को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। पक्ष की चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

देहरादून पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा

◆कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया स्वागत



हमारे संवाददाता

देहरादून। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के देहरादून आगमन पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पहुंच उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का अभिवादन करते हुए उनके उत्तराखंड आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की। असम के मुख्यमंत्री के देहरादून आगमन के अवसर पर मंत्री प्रदीप बत्रा ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस मुलाकात के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच आपसी सौहार्द और समन्वय की भावना भी देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के उत्तराखंड आगमन पर उनका अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं दीं।

महिला एसआई 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सतर्कता विभाग की टीम ने हरिद्वार जिले के रानीपुर थाने में तैनात महिला सहायक उपनिरीक्षक (एसएसआई) सोनिया को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एसएसआई ने शिकायतकर्ता से दूसरे पक्ष के साथ चल रहे लेन-देन के विवाद में समझौता कराकर मामला निपटाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद सतर्कता विभाग ने ट्रैप की कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, विभाग से शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रानीपुर थाने में नियुक्त एसएसआई सोनिया उससे मामले का निपटारा कराने के बदले 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रही हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सतर्कता विभाग ने इसकी जांच कराई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सेक्टर देहरादून के निर्देश पर ट्रैप टीम का गठन किया गया। इसके बाद सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की योजना बनाई। आज टीम ने निर्धारित रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए महिला एसएसआई सोनिया को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मचने की संभावना है। सतर्कता विभाग की ओर से मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान, 35 भवन स्वामियों का किया चालान

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने वृहद सत्यापन अभियान चलाकर 35 भवन स्वामियों का 83 पुलिस एक्ट में चालान किया।

आज यहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों एवं क्षेत्र में निवास कर रहे संदिग्धों/बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन तथा नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली पटेल नगर पर गठित अलग-अलग पुलिस टीमों द्वारा कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अलग-अलग स्थानों, लोहियानगर, चमनपुरी, ब्रह्मपुरी, ब्राह्मणवाला, पाम सिटी आदि क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों/किरायेदारों व आपराधिक



क पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्तियों के सत्यापन हेतु अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा 500 से अधिक किरायेदारों/बाहरी व्यक्तियों के साथ साथ पूर्व के आपराधिक घटनाओं में लिप्त/प्रकाश में आये/जमानत पर चल रहे 12 अभियुक्तों का भौतिक सत्यापन किया गया, इस दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े अभियुक्तों को किसी आपराधिक घटना में पुनः लिप्त मिलने पर सख्त वैधानिक

कार्यवाही की चेतावनी दी गयी। बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के दौरान किरायेदारों/घरेलू नौकरों का सत्यापन न कराने व अन्य अनियमितता मिलने पर पुलिस द्वारा 35 भवन स्वामियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनका 03 लाख 50 हजार रु० का जुर्माना किया गया। पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर लगाम लगाने के लिए थाना क्षेत्रान्तर्गत खाद्य पदार्थों का भंडारण करने वाले व्यक्तियों के साथ साथ डेयरी, गोदामों आदि जगहों पर भी खाद्य विभाग की टीम के साथ औचक छापेमारी की कार्रवाई की गई, इस दौरान पुलिस द्वारा 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हेतु थाने लाया गया है, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर पाबंदियों के पीछे कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आम नागरिकों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता !

संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित राजनीतिक प्रदर्शन से पहले जंतर-मंतर और नई दिल्ली के आसपास लागू अस्थायी पाबंदियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात व व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारु रखना भी उतना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से सुरक्षा संबंधी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

एडिशनल सीपी पीआरओ राजीव रंजन ने बताया कि जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि एक दिन के प्रदर्शन की अनुमति मिलने के बावजूद कथित तौर पर धरना करीब एक महीने तक जारी रहा। पुलिस के अनुसार, इस अवधि में 200 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दो हजार से अधिक लोगों की भागीदारी की सूचना मिली। हालात बिगड़ने पर झड़पें हुईं, जिनमें निर्दोष छात्र भी घायल हुए। पुलिस का कहना है कि पहले सामने आ चुके ऐसे हालात की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस बार पहले से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था

करना आवश्यक है। प्रेस विज्ञप्ति में बीते सप्ताह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों द्वारा दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबलों के साथ कथित छेड़छाड़ और मारपीट की घटनाओं को भी गंभीर चिंता का विषय बताया गया है। पुलिस के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात जवानों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और वहां से गुजरने वाले आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन स्थल की सीमित क्षमता का हवाला देते हुए कहा कि जंतर-मंतर अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र है, जहां एक समय में लगभग एक हजार लोगों के लिए ही सुरक्षित

व्यवस्था की जा सकती है। किसी भी स्थान पर भीड़ की संख्या तय करते समय उपलब्ध जगह, आपातकालीन सेवाओं की पहुंच, भीड़ नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ एक प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है। ऐसे में प्रदर्शन के अधिकार और शहर के सामान्य जनजीवन के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। राजधानी के निवासियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, यात्रियों और अन्य लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाना भी सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार
समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।

मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।